In most of the cases rebate has been given. In the remaining cases the rebate shall be adjusted through subsequent telephone bills.

(b) Rebate given so far is Rs. 8,59,588/-.

Statement

No. of telephones which remained out of order for more than 7 days.

s. No	Name of Place	June, 96	July, 96	Aug., 96
1.	Ahmedabad	5074	9631	194
2.	Surat	979	1518	715
3.	Bhavnagar	234	655	—
4.	Rajkot	1757	1774	—
5.	Vadodara	93	115	475
6.	Jamnagar	5	5	4
7.	Bharuch	100	125	565

NOTE: The no. of telephones out of order for more than 10 days is less than the figures given above for telephones faulty more than 7 days.

Profit earned by Paradip Port

3157. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the effort being made to reach the target of 9th Five Year Plan in respect of augmentation of Port capacity;

(b) the usual capacity level of different Ports including Paradip Port for the years 1993-94 and 1994-95; and"

(c) the profit earned by the Paradip Port in the years 1993-94 and 1994-95.

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATARAMAN): (a) During the 8th Plan 1992—97, a total number of 30 new major projects costing about Rs. 2147 crores have already been sanctioned. During first four years of 8th plan, additional capacity upto 8.23 million tonnes has since been created. During 1996-97, another 12.50 million tonnes of additional capacity is likely to be achieved.

(b) During 1993-94 and 1994-95, the capacity at various major ports was as under:

Capacity (in million tonnes)

	Name of the Port	1993-94	1994-95
1.	(a) Calcutta	6.75	6.75
	(b) Haldia	16.78	16-90
2.	Bombay	26.80	26.80
3.	J.L. Nehru	5.90	6.90
4.	Madras	22.07	22.07
5.	Cochin	10.66	10.80
6.	Vizag	23.05	23.35
7.	Kandla	20.80	20.80
8.	Mormugao	15.92	15.92
9.	Paradip	7.65	7.65
10	New Mangalore	9.55	9.65
11	Tuticorin	5.10	6.10
	Total	: 171.03	172.59

(c) The operating surplus by paradip port during the year 1993-94 and 1994-95 were Rs. 2790.51 lakhs and Rs.2287.71 lakhs respectively.

मधुबनी में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई विदेशी सहायता

3158. श्री रामदेव भंडारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान बिहार के मधुबनी जिले में स्वैच्छिक संगठनों को विदेशी संस्थाओं से प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी संस्थाओं के नाम और पता, उनके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता की धनराशि, उक्त सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के नाम तथा उनके द्वारा प्राप्त धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख) निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों वाली एसोसिएशनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से पहले, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकरण कराना या पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार से पंजीकृत/अनुमति प्राप्त एसोसिएशनों को वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के भीतर, निर्धारित प्रपत्र में अपना वार्षिक लेखा-जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें धन प्राप्ति और उपयोग के ब्यौरे देने होते हैं। इस प्रकार की एसोसिएशनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय के बारे में वर्ष 1994-95 तक की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां पहले ही

संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उस वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय देने वाले स्रोतों के नाम, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि, इस प्रकार का अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम होते हैं। चूंकि सूचना देने वाली 11,000 से अधिक इकाईयां हैं। अत: वर्ष 1995-96 के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि इनकी छंटाई और संकलन की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। वर्ष 1996-97 की सूचना अभी देय नहीं हुई है।

Optimum utilization of Water Resources in Orissa

3159. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the specific steps taken by Government for optimam utilisation of water resources in Orissa during Seventh and Eighth Five Year Plan;

(b) whether higher priority needed for the optimum utilization of the available water resources in different States; and

(c) to what extent the same has eben done in Orissa?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Modernisation of Irrigation Project in Andhra Pradesh

3160. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) Whether any proposal to modernise certain irrigation projects in Andhra Pradesh has been received by the Central Government;

(b) if so, the details thereof and the action taken thereon;

(c) whether the Central Government have provided any assistance for the proposal; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESWAR MISHRA): (a) and (b) 4 modernisation proposals namely Krishna Delta System modernisation, Kumool Ouddapah Canal Modernisation, Godavari Delta System Modernisation and Pennar Delta System Modernisation were received in the CWC for techno-economic appraisal. Out of these, Krishna Delta System Modernisation and Murnool Cuddapah canal Modernisation; have ben found acceptable by the Advisory Committee in April, 1996 and June 1996 respectively subject to obtaining environmental clearance from the Ministry of Environment & Forests and compliance of certain other observations by the State Government. The remaining 2 proposals have been sent back to the State Government for submission of modified proposals after compliance of observations of the CWC.

(c) and (d) The Central assistance is in the form of block loans and grants not tied to any project or the programme. No special Central assisance has been provided to the State Government for implmentation of these proposals.

किराये के परिसरों में कार्य करने वाले भारतीय मिशन

3161. श्री अजीत जोगी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों में भारतीय मिशन कार्य कर रहे हैं;

(ख) किराये के परिसरों में कार्य करने वाले भारतीय मिशनों की संख्या कितनी है;

(ग) इन परिसरों पर किराये के रूप में प्रति वर्ष औसतन कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(घ) निकट भविष्य में किन-किन देशों में भारतीय दूतावास परिसर बनाये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क) भारत सरकार ने 113 देशों में आवासी मिशन स्थापित किए हैं।

(ख) 58 मिशन किराये के परिसरों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान इन परिसरों पर औसत वार्षिक व्यय 10.22 करोड़ रुपये था।

(घ) निम्नलिखित देशों में भारतीय मिशनों के लिए परिसरों का अथवा मौजूदा परिसरों के विस्तार करने के लिए परिसरों का शीघ्र ही निर्माण किया जाएगा।

(i) रूसी परिसंघ

(ii) उजबैकिस्तान